कोविड-19
पर दूसरा विशेष अंक

खंड १६ नंबर २ अप्रैल २०२०

आरआईएस डायरी

-अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

महानिदेशक की ओर से

आरआईएस, कोविड–19 पर आरआईएस डायरी के विशेष अंक के इस दूसरे संस्करण को ला रहा है। इसमें हमारे विशिष्ट सहयोगियों के आलेख हैं: प्रोफेसर एस के मोहंती द्वारा ''कोविड 19 के विश्व व भारत पर प्रभाव: रोकथाम की रणनीतियाँ;'' डॉ भास्कर बालकृष्णन द्वारा ''कोविड–19 से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को मजबूत करे''; डॉ पी. के. आनंद और कृष्ण कुमार द्वारा ''कोविड–19 के दौर में भोजन व पोषण सुरक्षा''; ऑगस्टीन पीटर द्वारा ''कोविड 19: वैश्विक बहुपक्षीय संबंधों के लिए नई आशा''; तथा शुभोमय भट्टाचार्जी द्वारा ''कोविड–19 के लिए सुधार पैकेज''।

हमें यकीन है कि इन विशेष लेखों में दिए गए सुझाव उपयोगी पाए जाएंगे, खासकर ऐसे समय में जब हम वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवार, व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक मोर्चे पर कोविड–19 से पीड़ित मानव जाति के सामने मौजूद खतरे से निपटने के लिए रणनीति विकसित कर रहे हैं। हम आपके विचारों और प्रतिक्रिया से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।

सचिन चतुर्वेदी

कोविड–19 के विश्व व भारत पर प्रभाव: रोकथाम की रणनीतियाँ

एस के मोहन्ती

कोविड–19 के कारण पैदा हुआ वर्तमान वैश्विक संकट समकालीन वैश्विक इतिहास में अपने तरीके का पहला संकट है। इस वैश्विक संकट के परिणाम धीरे–धीरे सामने आ रहे हैं जिनमें भारी संख्या में मौतें, भविष्य में अप्रत्याशित मौतों की आशंका, बेरोजगारी में वृद्धि, विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी से आ रही गिरावट, मंदी का लंबा दौर, आदि शामिल हैं। ये सब विश्व अर्थव्यवस्था को अनिश्चितता की स्थिति में ले जा रहे हैं, जहां से संकट–पूर्व के स्तर पर लौटने में वर्षों लगेंगे।

बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस पहली बार 17 नवंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत में पाया गया था और वायरस के तेजी से प्रसार का मुकाबला करने के लिए 23 जनवरी 2020 से यह प्रांत तालाबन्दी में था। इस महामारी का प्रकोप चीन में कम हो गया है, लेकिन दुनिया भर में यह महामारी जंगल की आग की तरह फैल गई है। 12 अप्रैल 2020 तक वैश्विक स्तर पर 17.8 लाख मामले सामने आए हैं जिसमें 1.1 लाख मौतें हुई और 4.1 लाख लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। अमेरिका ने 5.33 लाख पुष्ट मामलों

प्रोफेसर, आरआईएस

की सूचना दी है, 32 हजार मरीज इलाज करवा कर ठीक हुए और 20.6 हजार मौतें हुईं। यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों के लिए स्थिति गंभीर बनी हुई है। जनवरी 2020 के अंत तक, कोरोनोवायरस की अपने यहां मौजूदगी के बारे में 20 देशों ने सूचना दी थी फरवरी में 35 नए देश इस सूची में शामिल हुए और मार्च और अप्रैल के बाद के महीनों में 155 और देश इस सूची में शामिल हुए। महामारी फैलने की प्रतिक्रिया दुनिया भर में एक जैसी थी।

कोविड–19 का गंभीर प्रभाव हो रहा है और विश्व अर्थव्यवस्था 2020 में सबसे खराब आर्थिक गिरावट की ओर बढ़ रही है। विश्व अर्थव्यवस्था की जोरदार वापसी के बारे में एक मजबूत उम्मीद के विपरीत, 2019 में विकास के प्रदर्शन को निराशाजनक स्तर पर लाने के लिए यह नया वायरस जिम्मेदार है। आईएमएफ ने 2008 में दुनिया में बड़ी मंदी के दौरान की स्थिति की तुलना में मौजूदा स्थिति को बदतर के रूप में वर्णित किया है। इसने 2019 में विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध जारी है और नवंबर के मध्य से महामारी के कारण पैदा हुई इस स्थिति ने 2019 में विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि की उम्मीद को कम कर दिया।

चूंकि विश्व अर्थव्यवस्था से कोविड–19 के बाहर होने की संभावना क्षीण है, इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का सटीक आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। विश्व की गंभीर तस्वीर को ध्यान में रखते हुए, विश्व व्यापार संगठन के आकलन के अनुसार कोविड–19 से पैदा हुई आर्थिक स्थिति 1930 के बाद की मंदी की स्थिति से भी खराब है।

2020 में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अलावा, एशियाई महाद्वीप को जबरदस्त झटका लगने की संभावना है। विश्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार, चीन की विकास दर 2019 में 6.1 प्रतिशत से घटकर 2020 में 2.3 प्रतिशत रहने की संभावना है। विकासशील पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की विकास दर 2020 में 2.1 प्रतिशत रहने की संभावना है जबकि 2019 में यह दर 5.8 प्रतिशत थी।

दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध और ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) के चीन के साथ मजबूत संबंधों के कारण तनाव में हैं। कोविड–19 के कारण उनका संबंध और अधिक दबाव में है, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को गहरी मंदी में धकेल सकता है। इस बीमारी के फैलने से विश्व स्तर पर कई क्षेत्रों के प्रभावित होने की संभावना है और दक्षिण एशियाई देश भी इससे प्रभावित होंगे, इस संदर्भ में वे अपवाद नहीं हैं। विश्व बैंक के अनुसार, जीडीपी वृद्धि के संकुचन से इस क्षेत्र के 11 मिलियन लोग गरीबी के जाल में फंसने के कगार पर हैं।

ऐसी स्थिति में जहां कोविड–19 का प्रसार जारी है, विश्व अर्थव्यवस्था के 2008 वित्तीय संकट से भी बदतर स्तर तक जाने की उम्मीद है, और इससे सबसे अधिक प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। कोविड–19 के बाद की अवधि का प्रभाव वैश्विक व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, वैश्विक व्यापार में 2020 में 13 प्रतिशत से 32 प्रतिशत के बीच गिरावट आ सकती है, क्योंकि कोरोनो वायरस से जुड़े नकारात्मक जोखिम अभी अस्पष्ट हैं।

वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति हो सकता है इतनी खराब न हो, इस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 21 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रभावित अर्थव्यवस्थाएं चुनौती से किस प्रकार और कितनी अवधि में निपटती हैं। माल के व्यापार और सेवाओं में व्यापार पर इस बीमारी का प्रभाव महसूस होगा। जीवीसी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सटीक उपकरण, रसायन, चिकित्सा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), पर्यटन, बीमा, परिवहन, आईसीटी, वित्त, आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापार पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। वैश्विक व्यापार में 2020 में तेजी से गिरावट आने की संभावना है और इसके प्रमुख कारण हैं परिवहन, यात्रा, निर्यात पर प्रतिबंध तथा विनिर्माण क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक क्षमता।

भारत में कोविड–19 के मामले अपेक्षाकृत देरी से आए,यहां इस रोग का पहला मामला 30 जनवरी, 2020 को सामने आया था। वायरल संक्रमण के बहुत शुरुआती चरण में, देश ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। नीतिगत प्रतिक्रियाओं के एक क्रम में, भारत ने बीमारी के प्रसार को दूर करने के लिए कई उपायों की घोषणा की और आर्थिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखा। मौजूदा हालात में भारत का व्यापार परिदृश्य बहुत नाजुक है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई सेक्टरों में आर्थिक गतिविधियों को यहां जिस प्रकार सीमित कर दिया गया है, उससे 2020 में भारत के निर्यात में 18 से 35 प्रतिशत गिरावट आने की संभावना है। हालांकि यह गिरावट कितनी होगी यह तालाबन्दी की अवधि पर भी निर्भर करेगा और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किस हद तक सेक्टरों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। राज्य सरकारों की सलाह से, केंद्र अर्थव्यवस्था में सामान्य आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए तालाबन्दी अवधि बढ़ाने और कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को खोलने पर विचार कर रहा है।

क्या तालाबंदी के बाद अर्थशास्त्री कीन्स के सिद्धांतों की वापसी होगी

सचिन चतुर्वेदी

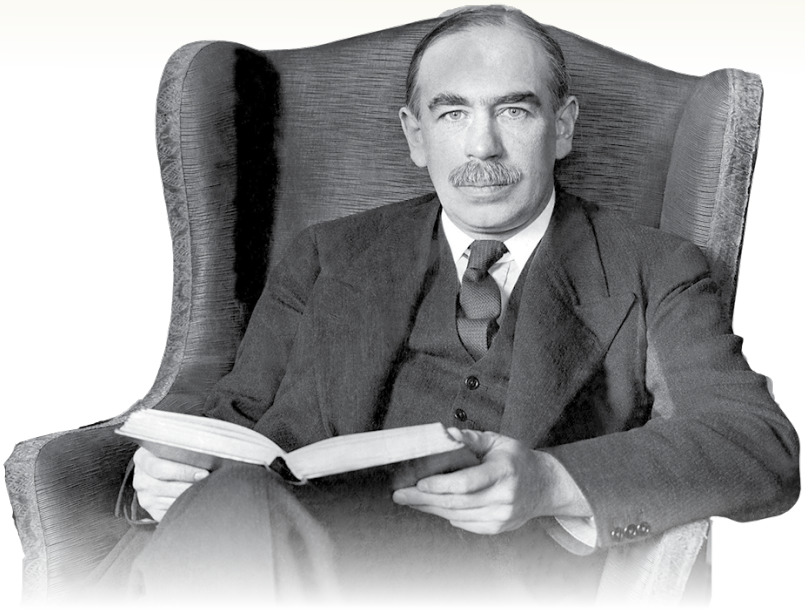

अपनी क्लासिक पुस्तक में, रॉबर्ट स्किडेल्स्की ने 2008–09 की मंदी के बाद अमेरिका को कीन्स के आर्थिक सिद्धांतों पर दोबारा अमल का सुझाव दिया था। इस पुस्तक में मूल रूप से राज्य और बाजार के बीच संबंधों को पुनः परिभाषित किया गया और कीन्स के आर्थिक सिद्धांतों के नजरिए से राज्य और बाजार के बीच नाजुक संतुलन कायम करने के बारे में चर्चा की। नतीजन सलाह यह दी गई कि राजकोषीय प्रोत्साहन और विस्तारवादी मौद्रिक नीति के रूप में दो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कीन्स को नव–शास्त्रीय यानी नियो–क्लासिकल और शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अलग करता है। यह दृष्टिकोण उस समय सबसे अधिक प्रासंगिक है, जब आर्थिक नीति को जोखिम और अनिश्चितता के बीच अंतर स्थापित करना पड़ता है।

नीति निर्माताओं ने भी झट से इन सुझावों को स्वीकार कर लिया, एक बार तो ऐसा लगा कि फ्रीडमैन के सुझावों को ठंडे बस्ते में डालकर कीन्स के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया है। अमेरिका में यह कीन्स की दूसरी वापसी थी। 1931 में, कीन्स ने प्रति–चक्रीय सार्वजनिक नीति की वकालत की थी, जिसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया था। इसने उस समय भी अर्थव्यवस्था को संकट से उबार लिया था।

कोविड–19 के साथ ही दुनिया वापिस उस स्थिति में पहुंच गई है जहां मांग व पूर्ति दोनों ही बुरी तरह से गिरे हैं। क्या अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कीन्स की वापसी होगी? 210 से अधिक देश इससे प्रभावित हैं, 18 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है तथा एक लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हाल ही के समय में यह अब तक की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है।

महानिदेशक, आरआईएस

हाल ही में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इसे "वैश्विक वित्तीय संकट से भी बदतर" बताया। कुछ अनुमानों के अनुसार, 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी जो कि 2008–09 की मंदी की तुलना में भी कई गुना अधिक है।

कोविड संकट के साथ, कई सरकारें पहले ही राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के साथ आगे आ चुकी हैं। लगभग सभी जी –7 देशों ने पहले ही इस बारे में विस्तार से घोषणाएं की हैं।

भारतीय पैकेज

कोविड के साथ ही चक्रीय व ढांचागत चुनौतियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था के लिए व्यवहारिक नीतियों के पूरक कीन्स के आर्थिक सिद्धांतों का परिप्रेक्ष्य होगा ।

हाल ही के महीनों में आरबीआई में एक अच्छी बात यह हुई है कि उसका एक मात्र एजेंडा अब मुद्रास्फीति पर केंद्रित नहीं है और न ही अब वह बेसल नियमों पर अमल करने पर पूरी तरहं केंद्रित है। यह अहसास कि बैंकों और मौद्रिक नीतियों का क्रियान्वयन अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है और यह व्यापक विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है, एक उत्साहजनक संकेत है।

भारत द्वारा घोषित कुछ शुरूआती कदमों में पहले से ही वृहद–राजकोषीय ढांचे के पुनरुद्धार पर निरंतर ध्यान देने के साथ बड़े पैमाने पर राजकोषीय व्यय शामिल हैं। एफआरबीएम लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत था, केंद्र सरकार का यह लक्ष्य इस प्रक्रिया में संभवतः पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि, स्थानीय स्तर पर उप–राष्ट्रीय संस्थाओं को अपने काम–काज के लिए आवश्यक स्वतंत्रता दिए जाने पर नीति को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा।

हालांकि, जैसा कि कीन्स ने सुझाव दिया था, यह आवश्यक है कि राज्य व्यय को पर्याप्त रोजगार सृजन के साथ–साथ पूंजीगत संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यदि एफआरबीएम की गहन समीक्षा की जाती है, तो हमें उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सभी निर्देशों को देश में आपातकाल जैसी स्थिति को देखते हुए अस्थायी रूप से अनदेखा किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने विशिष्ट स्थानीय संदर्भ में कुछ वैश्विक मानदंडों के स्थगन पर ठीक ही बल दिया है।

सामाजिक सामंजस्य

पिछले कुछ बजटों में सरकार ने ग्रामीण विकास और कृषि के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। कोविड–19 के उपरांत की नीतियों को 'सामाजिक सामंजस्य' के लिए कृषि पर ध्यान

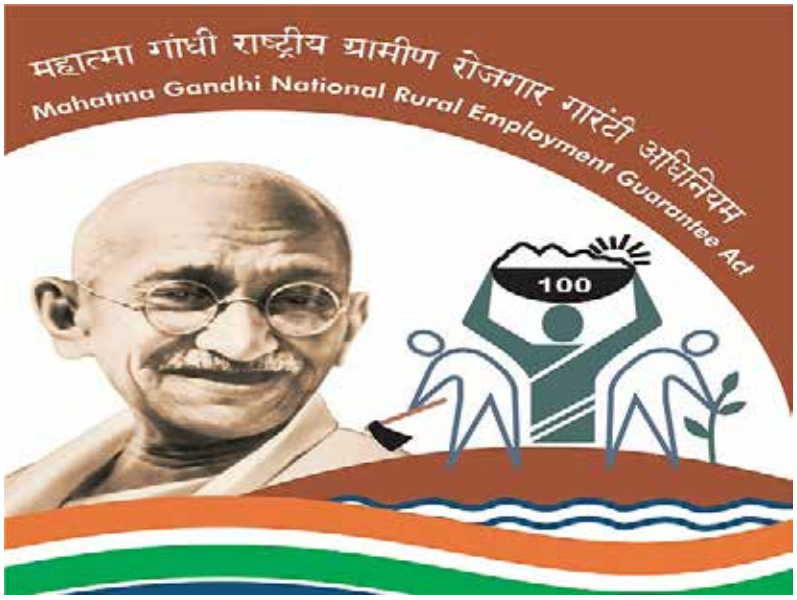

केंद्रित करना चाहिए, जिस पर कीन्स ने बात की थी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुलता और विदेशी व्यापार से दबाव को कम करने के लिए भी आवश्यक है जिसे भूमंडलीकरण के विपरीत दिशा में जाने की प्रवृत्ति का खामियाजा भुगतना होगा, जो निकट भविष्य में होने की संभावना है।

पिछले कुछ वर्षों में, विकास व्यय का हिस्सा (आधार वर्ष) और 2019 के बीच 21 प्रतिशत बढ़ गया, 2019 में यह राशि 114 कार्यक्रमों में 78 लाख 14 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इन कार्यक्रमों में से, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में उभरा है। अपने दिशानिर्देशों को बदलने के साथ, यह कार्यक्रम गुणवत्ता पूर्ण संपत्ति बनाने के लिए योगदान दे रहा है और साथ ही लगभग 7.97 करोड़ लोगों को मजदूरी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जो कि कार्यक्रम लोकार्पण होने के बाद अब सबसे अधिक है। एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि इस कार्यक्रम ने अपनी पहुंच का निचले स्तर पर विस्तार भी किया है। 2.63 लाख ग्राम पंचायतों में से केवल 9,144 पंचायतों ने इस कार्यक्रम के तहत कोई खर्च नहीं किया है। 2015 में यह संख्या 40 हजार के करीब थी। कहने की जरूरत नहीं है, कि इस योजना में अनैच्छिक बेरोजगारी के खतरों को कम करने और पूर्ण रोजगार संतुलन के करीब जाने के लिए भीतर से प्रभावी मांग को बढ़ाने की क्षमता है, भले ही इसे शत प्रतिशत प्राप्त न किया जा सके।

कीन्स की खासियत यह है कि उसने आर्थिक शासन की कोई भी एक विशिष्ट प्रणाली निरूपित नहीं की है। एक प्रणाली, जो उसके सभी लेखन में प्रासंगिक है, वह है पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए समग्र मांग को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों की भूमिका।

कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को मजबूत करें

भास्कर बालाकृष्णन

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में मुख्य समन्वय एजेंसी है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जो उचित ही है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड–19 से निपटने के प्रयासों की कुछ आलोचना की गई है और यहां तक कि महानिदेशक के इस्तीफे के लिए भी मांग हुई है । यह आलोचना न्यायसंगत नहीं है और इस महत्वपूर्ण समय पर इस संगठन के सदस्य देशों के लिए इसकी भूमिका को सक्रिय रूप से मजबूत करना आवश्यक है।

पिछले कुछ सालों से कुछ देश, खासकर अमेरिका व यूके, डब्ल्यूएचओ की आलोचना करते रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि डब्ल्यूएचओ ने (विकासशील देशों की आवश्यकताओं व कुछ गैर सरकारी संगठनों की मांग पर) कुछ प्रयासों की पैरवी की है मसलन आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, स्तन के दूध के विकल्पों को हटाना, तंबाकू और शराब के सेवन के खिलाफ अभियान, आदि।

इन प्रयासों को बड़ी फार्मा कंपनियों और कुछ प्रमुख लॉबी और उद्योगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में देखा जाता है। यह लड़ाई अमेरिका जैसे कुछ देशों के घरेलू एजेंडे में भी तेज हो गई है। डब्ल्यूएचओ पर हमले, बजट और कार्यक्रमों में कटौती, सुधारों के लिए लगातार मांग, संसाधनों के योगदान की वापसी यां उसे रोकने की धमकियों आदि के रूप में सामने आए हैं। जवाब में, डब्ल्यूएचओ ने एक स्वतंत्र समीक्षा और सलाहकार समिति (आईओएसी) की स्थापना की है, और सदस्य देशों ने डब्ल्यूएचओ के रूपांतरण एजेंडा अपनाया है।

यह सच है कि चीन डब्ल्यूएचओ में एक प्रभावशाली सदस्य बन गया है। इससे पहले के महानिदेशक चीन (हांगकांग) से

विज्ञान राजनय फेलो, आरआईएस

थे जिन्होंने 2006–2017 के दौरान संगठन का नेतृत्व किया। डब्लूएचओ के नियमित बजट में चीन का योगदान 2019–21 के लिए 12 प्रतिशत बढ़कर, केवल अमेरिका (22 प्रतिशत के साथ) दूसरे स्थान पर है। इससे पूरी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में चीन के प्रभाव में वृद्धि हुई है। एफएओ, यूएनआईडीओ, आईसीएओ और आईटीयू जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के मुखिया चीन की मर्जी से चुने गए हैं जो उसके प्रभाव को रेखांकित करते हैं । डब्ल्यूआईपीओ के प्रमुख के पद पर कब्जा करने के उसके प्रयास अमेरिका के नेतृत्व में एक जोरदार अभियान के कारण पराजित हुए। चीन अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अपने बढ़ते हुए प्रभाव का लाभ उठाता है, जैसे कि 'बेल्ट एंड रोड' पहल को बढ़ावा देना, ताइवान को व्यवस्था से बाहर रखना, आदि। इस संदर्भ में आगे देखना होगा कि कि संयुक्त राष्ट्र के बजट में बड़ा योगदान देने वाले कई अन्य देश क्या कर रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी मंडल[1] की बैठक तीन से आठ फरवरी 2020 के दौरान हुई थी, 7 फरवरी को कोविड–19 के प्रकोप पर महानिदेशक और उनकी टीम ने बोर्ड को जानकारी दी। डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन तैयारियों की एक विस्तृत चर्चा 7 फरवरी को हुई और कई प्रतिभागियों ने कोविड–19 के प्रकोप के लिए डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया की प्रशंसा की। महानिदेशक ने एक गंभीर वैश्विक प्रकोप, चिकित्सा उपकरणों और पीपीई की कमी संबंधित खतरों की चेतावनी दी, और डेटा साझा करने में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया।

उस समय यह प्रकोप मुख्य रूप से केवल 24 अन्य देशों के मामलों वाले चीन, हुबेई प्रांत तक सीमित था। बोर्ड के सदस्यों ने मई 2020 में आगामी विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाया। आश्चर्यजनक रूप से इस मसौदे में कोविड–19 के प्रकोप का उल्लेख नहीं है, बल्कि उसमें सामान्य रूप से स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए डब्ल्यूएचओ की तैयारियों से संबंधित चर्चा की गई। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का संबंध था, बोर्ड के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों से परे जाने के लिए तैयार नहीं थे । पूर्व में हुई गतिविधियों के संदर्भ में किसी को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि एक महामारी की स्थिति की जल्द घोषणा, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को स्थगित करने में देरी नहीं होनी चाहिए।

बीती 11–12 फरवरी को डब्ल्यूएचओ व ग्लोपिड–आर (संक्रामक रोग की तैयारी के लिए वैश्विक अनुसंधान सहयोग) के साथ मिलकर, इन नए कोरोना वायरस के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की योजना बनाने के लिए एक वैश्विक अनुसंधान और नवाचार मंच का आयोजन किया। 300 से अधिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसमें व्यक्तिगत और ऑनलाइन भाग लिया और आठ बिंदुओं वाली कार्य योजना में वैश्विक अनुसंधान प्राथमिकताओं के एक समूह पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद, 4 मार्च को, डब्ल्यूएचओ द्वारा 96 पृष्ठ की भविष्य की एक विस्तृत शोध योजना का दस्तावेज जारी किया गया। यह वैश्विक समन्वित अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है।

73 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा[2] 17–23 मई 2020 के लिए निर्धारित है। मई 2020 में इस सभा को आयोजित करने का मतलब है सभी स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का जिनेवा में एक समय में वहां उपस्थिति होना, वह भी ऐसे समय में जब वे कोविड–19 के प्रकोप से निपटने में व्यस्त हैं। शायद इस बैठक को स्थगित कर दिया जाना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्रियों को घरेलु स्तर पर इस स्थिति से निपटने पर ध्यान देना चाहिए। स्विट्जरलैंड खुद कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और जिनेवा में कुछ 3000 प्रतिभागियों की यात्रा जोखिम भरा है। एक विकल्प के रूप में पहली बार इस बैठक को ऑनलाइन भी आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य सभा के इस स्थगित सत्र को कोविड–19 के प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक समन्वित प्रतिक्रियाओं का दृढ़ता से समर्थन करना चाहिए, जिसमें बीमारी की वापसी से निपटने और इसे खत्म करने के लिए वैश्विक दीर्घकालिक अभियान भी शामिल है। इस महामारी के प्रकोप की अभूतपूर्व प्रकृति को देखते हुए इस अवसर पर कोविड–19 पर एक विशेष घोषणा उपयुक्त होगी।

इस अवसर पर, डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व और विशेष रूप से महानिदेशक पर हमले, केवल कोविड–19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को कमजोर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का ध्यान इस महामारी के प्रकोप को कम करने और उसे सीमित करने पर होना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार शोध के माध्यम से इसके उपचार के लिए सस्ते और प्रभावी टीके विकसित करने के प्रयासों का दीर्घकालिक समर्थन किया जा सकता है। इस बात की काफी संभावना है कि यह बीमारी हमारे साथ बनी रहेगी और भविष्य में फिर से इसकी वापसी होगी। ऐसे में हमें उक्त लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी होगी

संदर्भ

[1] बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं। तीन साल के लिए ये 34 देश बोर्ड पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखते होते हैं। बोर्ड के सदस्य डब्ल्यूएचओ के 6 क्षेत्रों से आते हैं – अफ्रीका (7), अमेरिका (6), यूरोप (8), पश्चिमी प्रशांत (5), पूर्वी भूमध्यसागरीय (5), दक्षिण पूर्व एशिया (3)।

[2] भारत दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आता है और डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय की मेजबानी करता है।

कोविड–19 के दौर में भोजन व पोषण सुरक्षा

पी. के. आनंद

कृष्ण कुमार

कोविड–19 के मद्देनजर प्रचलित नियमों में लचीलेपन तथा स्थानीय समाधानों के आधार पर विकल्पों की आवश्यकता होती है। इस पृष्ठभूमि में खाद्य और पोषण सुरक्षा के मोर्चे पर स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, इसमें प्रमुख चुनौतियों को शामिल किया जाता है, प्रतिक्रियाओं और कुछ निष्कर्षों को जोड़ा जाता है और आगे बढ़ाया जाता है।

अच्छी उपज

वर्तमान आकलन के अनुसार रबी की फसल पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने की आशंका नहीं है। इस बीच वर्ष 2019–20 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत में खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 291.95 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.74 प्रतिशत अधिक है। गौरतलब है कि वर्ष 2018–19 में खाद्यान्न उत्पादन 285.21 मिलियन टन रहा था। इसके अलावा, 2019–20 के दौरान उत्पादन पांच साल के औसत (2013–14 से 2017–18) के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 26.20 मिलियन टन अधिक है[1]। सब्जियों, फलों, दालों और दूध के उत्पादन में भारत अग्रणी देश है इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इन वस्तुओं की उपलब्धता भी पर्याप्त है।

पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडार

भारत के खाद्य अनाज स्टॉक में मासिक वितरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिचालन स्टॉक शामिल हैं, और खरीद में कमी को पूरा करने या आपदा से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा भंडार हैं। अप्रत्याशित कोविड–19 महामारी के बीच, यह एक तथ्य है कि खरीदे गए स्टॉक का स्तर, अगर उचित ढंग से संग्रहित है और ठीक से भेजा जाता है, तो निश्चित रूप से यह देश की समग्र मांग को पूरा कर सकता है। विशेष रूप

विजिटिंग फेलो, आरआईएस

से, तालाबन्दी अवधि के दौरान निरंतर माल ढुलाई, जो यात्री ट्रेनों के ठहराव के कारण कम समय लेती है, तालाबन्दी के बाद पहले 13 दिनों में जारी रही। एफसीआई ने तालाबन्दी के दौरान प्रति–दिन औसतन 1.41 लाख मीट्रिक टन अनाज को भेजा, जबकि तालाबन्दी से पहले यह दैनिक औसत लगभग 0.8 लाख मीट्रिक टन था। इसके अलावा एफसीआई ने लचीला रुख अपनाते हुए 13 राज्यों में 1.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 8 राज्यों में 1.32 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया है, जिसमें गेहूं के आटे और अन्य गेहूं उत्पादों के निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया गया गेहूं भी शामिल हैं। यह आपूर्ति संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किए गए आकलन पर आधारित है।

पिछले चार सालों में 2016 से 2019 तक चावल, गेहूं, मिल में जाने से पहले का धान तथा मोटे अनाज का एफसीआई भंडार अधिकतम रहा है। चित्र 1 में वर्ष 2016 से 2019 के बीच पहली तीन मदों के अधिकतम स्टॉक का संकेत है, इसके अलावा इसमें 2020 के जनवरी, फरवरी, मार्च के मासिक स्टॉक की जानकारी भी है। इसमें मोटे अनाज शामिल नहीं हैं जिनका स्टॉक मार्च 2020[2] में 24000 मीट्रिक टन था। सौभाग्यवश कोविड–19 के भारत को प्रभावित करने से पहले जनवरी 2020 में एफसीआई का स्टॉक जनवरी 2019 की तुलना में चावल के लिए 30 प्रतिशत, गेहूं के लिए 21 प्रतिशत, मिल में जाने से पहले के धान के लिए 2 प्रतिशत तथा मोटे अनाज के लिए 61 प्रतिशत अधिक था[3]।

बड़ी चुनौतियां

परीक्षा की इस घड़ी में, घबराहट में की जा रही खरीद सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, जिसे संभालने के लिए निर्बाध आपूर्ति लाइनें और खरीदने के लिए अधिक घंटों की छूट स्थिति को बेहतर बना सकती है। उपभोक्ताओं के बीच बेहतर जागरूकता पैदा करने की भी आवश्यकता है ताकि वे आवश्यकता से अधिक स्टॉक न जमा करें जिससे मांग में अप्रत्याशित वृद्धि से बचा जा सके। इसके अलावा, खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन की कटाई केवल तभी की जा सकती है यदि आवश्यक श्रमशक्ति, कृषि मजदूरों, और फसल कटाई और थ्रेशिंग की सुविधा तालाबन्दी और उसके बाद की अवधि के दौरान उपलब्ध हो।

स्पष्ट रूप से फसलों को खेतों में अधिक समय तक खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इससे अनाज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तथा कटाई के बाद (कृषि क्षेत्रों में गिरने वाले अनाज की संभावना के कारण) बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे पहले से ही आय, स्वास्थ्य और किसानों के कल्याण पर पड़ने वाला प्रभाव और गहरा होगा। श्रमिक संकट एक महत्वपूर्ण अड़चन है क्योंकि प्रवासी श्रमिक खेतों पर उपलब्ध नहीं है। संयुक्त कटाई का गहन उपयोग, दुर्भाग्य से श्रमिकों के लिए मजदूरी की संभावनाओं को कम करता है।

खाद्य और पोषण सुरक्षा के मोर्चे पर कृषि श्रमिकों और पोषण कार्यकर्ताओं की आंशिक आवाजाही की अनुमति देने के लिए एक अंशकालिक योजना का गठन सबसे बड़ी प्रशासनिक

एफसीआई स्टॉक्सः चावल गेहूं धान (2016 से 19 शीर्ष स्तर) और जनवरी–मार्च 2020 (लाख मीट्रिक टन)

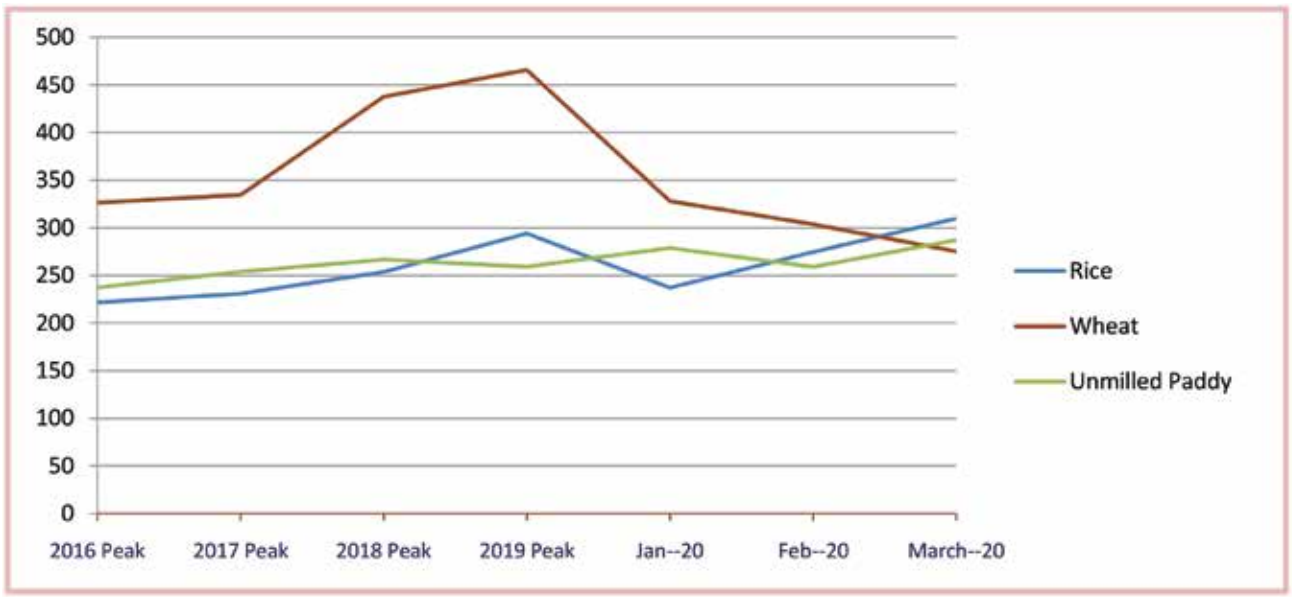

स्त्रोतः एफसीआई

चुनौती है। 'हॉट स्पाट्स' के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए जिला और उप–जिला स्तर पर स्थानीय समाधान, कमजोर वर्गों को भोजन और पोषण प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। खाद्यान्न वितरण, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिनमें राशन कार्ड धारक भी शामिल हैं एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मजदूरी के अभाव में कम दरों पर भी पीडीएस से खाद्यान्न खरीदना एक और बड़ी चुनौती है।

इसके अलावा, आगामी खरीफ की फसल को बढ़ाने की चुनौती विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिशा में खेती के लिए आवश्यक चीजों की व्यवस्था मसलन बीज, विशेष रूप से देश भर में उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का उत्पादन, परिवहन, वितरण और ऋण एक प्रमुख अल्पकालिक चुनौती है।

सरकार की प्रतिक्रिया

कोविड–19 के लिए सरकार की प्रतिक्रिया जेएएम त्रिमूर्ति, पेंशन योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम कृषि बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, आदि जैसे कई पहले से आरंभ की गई योजनाओं में तेजी लाने पर आधारित है। ठीक समय पर आवंटन राशि में वृद्धि तथा स्थानीय भाषाओं में परमर्श जारी कर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और आईसीएआर, तथा राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में उनके समकक्ष संस्थानों ने उपयुक्त कदम उठाए हैं।

इन सलाहों के दायरे में भोजन और पोषण सुरक्षा श्रृंखला का संपूर्ण वृत्त शामिल है। ये और वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा, किसानों और श्रमिकों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, कृषि मंत्रालय ने भी उन्हें दी गई छूट के ठीक से अनुपालन का आह्वान किया है, इस संदर्भ में नियमित निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। एक सरकारी बयान[4] के अनुसार, 1600 से अधिक सब्जी व फल मंडियां काम कर रही हैं और अधिक आगे चलेंगी। इन सलाहों के मूल में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है, जिसका प्रमाण यह है कि बड़े पैमाने पर कीमतों में कोई उछाल नहीं है।

गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसले हालांकि उप–दीर्घकालिक–औसत तापमान के कारण इस वर्ष थोड़ी देर से परिपक्व हुई, लेकिन उनकी कटाई को अब स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद, पंजाब और हरियाणा में कुल मिलाकर बेहतर फसल हुई है। राज्य, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलेवार स्तर पर इन बातों का संज्ञान लेना चाहिये। पंजाब और हरियाणा में बम्पर पैदावार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में अच्छी फसल और अन्य राज्यों में फसल की स्थिति बहुत पीछे नहीं है। जहां भी हार्वेस्टर मशीनें उपलब्ध नहीं हैं या किराए पर बाहर काम नहीं दिया जा सकता है वहां हाथों से कटाई आवश्यक है, विभिन्न व्यक्ति फसल की विभिन्न पंक्तियों में दूरी रख कर कर सकते हैं। ऐसे में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना, बार–बार हाथ धोना और फेस मास्क के लिए प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना संभव है। स्थानीयकरण के एक भाग के रूप में, यहां तक कि इस्तेमाल किए गए जूट के गन्ने के थैलों को 5 प्रतिशत नीम के घोल आदि में भिगोकर उपचारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत रूप से छुए गए कृषि यंत्रों की सतहों को साबुन के पानी से धोए जाने तक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। फसल कटाई, पैकिंग, भंडारण, खरीद और विपणन में योगदान देने के लिए अधिकृत रूप से दिए जा रहे परामर्श का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें अब प्रत्यक्ष विपणन भी शामिल है।

कैलोरी संबंधित आवश्यकताएं स्वच्छ, पौष्टिक और सस्ता भोजन व पोषण सुरक्षा ढांचे का एक हिस्सा हैं। इसमें अनाज के अलावा सब्जियां, फल, दूध, मछली, मसाले, चीनी आदि शामिल होने चाहिए। विशेष रूप से, मोटे अनाज, जिसे अब 'बेहतरीन अनाज' माना जाता है तथा जिसे पोषणयुक्त अनाज कहा जाता है, को कम मानव शक्ति के साथ, परती और नीची भूमि में उगाया जा सकता है, इसे कम उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक होते हैं। इनका कम ग्लाइसेमिक सूचकांक मधुमेह वाले लोगों के लिए इसे खास तौर पर फायदेमंद बनाता है, गौरतलब है कि कोविड–19 के संदर्भ में मधुमेह को जान का खतरा पैदा करने वाली बीमारी माना जाता है। मोटे अनाजों के लिए ज्यादा भूमि का आवंटन संसाधनों की कमी के समय में एक आवश्यक आवंटन रणनीति हो सकती है।

खाद्य मंहगाई पर अंकुश

घबराहट व डर में वस्तुओं की कमी की आशंका से उनकी ज्यादा खरीद करने से पैदा हुई कमी वास्तविक कमी से कहीं अधिक खतरनाक है। प्रत्येक जिले के लिए सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षणों के माध्यम स्थानीय से स्वाद और प्राथमिकताएं, जो देश भर में सब्जियों, दालों, पोषक तत्वों–अनाजों के साथ–साथ चावल और गेहूं की किस्मों के लिए अलग–अलग होती हैं, का पुनः आकलन करना चाहिए। मांग पक्ष की बात करें तो एमपीसीई प्रोफाइल, पहले से कमजोर हुई क्रय शक्ति, अधिक शेल्फ लाइफ को उचित महत्व दें। उसके साथ के साथ, मातहत खरीद शक्ति, मांग पक्ष पर शेल्फ जीवन के लिए बढ़ाई गई आवश्यक आपूर्ति पक्ष में इनपुट की उपलब्धता (पर्याप्त गुणवत्ता के बीज सहित, और उर्वरक, कीटनाशक, आदि, स्थानीय समाधान द्वारा पूरक), खेती को लेकर चुनौतियां, आपूर्ति और प्रसंस्करण श्रृंखला पर ध्यान देना होगा। साथ ही स्वच्छता और सुरक्षित मानव स्पर्श और व डिस्टेंसिंग को भी सुनिश्चित करना होगा। सब्जियों और फलों को सामान्य तौर पर जिस समय तोड़ने की आवश्यकता होती है उस समय इन क्षेत्रों में तालाबन्दी का उठाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है कि आपूर्ति लाइन को बनाए रखा जा सके।

मिड–डे–मील योजना और आईसीडीएस से संबंधित तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सहायता समूहों या ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में सीएसओ या निगम निकायों की मदद से स्कूल व आंगनवाड़ी को तालमेल तथा नई सोच के साथ काम करना चाहिए। केंद्र व राज्य में मानव संसाधन विकास और महिला व बाल विकास विभाग से संबंधित मंत्रालयों की भूमिका अपेक्षित अनाज, तेल इत्यादि के प्रावधान को सुनिश्चित करने तथा मसालों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाने में होनी चाहिए। स्कूल में उगाई जाने वाली सब्जियों को सब्जियों, फलों, दूध, दालों आदि के साथ पूरक रूप में लिया जा सकता है। स्कूल के दिनों में इस योजना को चलाने के बजाए, इसे स्कूल की छुट्टियों सहित सभी दिनों तक विस्तारित किया जाना चाहिए, भले ही कक्षाएं बंद हों। 'हॉट स्पॉट्स' घोषित किए स्थानों पर गर्म भोजन या राशन की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए ऑपरेशन को छोटा किया जाना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं या तीन साल से कम उम्र के बच्चों को घर के लिए राशन (टीएचआर) उपलब्ध करवाए जाने वाले वर्गों से किसी भी हालत में बाहर नहीं रखना चाहिए।

घर और स्कूल के किचन गार्डन, ग्राम स्तर पर दूध का उत्पादन, दूध पाउडर का निर्माण करने वाले कारखाने और दूध और दूध से बने पैकेज वाले उत्पाद, संरक्षित और प्रसंस्कृत वस्तुओं को उस जिला स्तरीय फ्रेमवर्क का हिस्सा होना चाहिए जो कोविड–19 से निपटने के लिए बनाया गया है। इनमें निजी हितधारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामुदायिक रसोई में गर्म पकाए गए भोजन को वहां से कहीं और ले जाने यानी 'टेक अवे' का विकल्प होना चाहिए। सभी को यह प्रतिबद्धता जाहिर करनी होगी कि 'अनाज का एक दाना भी बेकार न जाए'। यह एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इसी संदर्भ में सामाजिक भौतिक दूरी के बीच सामाजिक संबंधों की मजबूती भी कसौटी पर कसी जाएगी।

इसके साथ ही आने वाली खरीफ की फसल के लिए एक मजबूत योजना बनानी होगी ताकि मानसून कमजोर भी रहे तो भी देश प्रभावित न हो। यह इस मायने में भी परीक्षा की घड़ी है कि सुनिश्चित किया जाए कि कोई एसडीजी की भावना से अनछुआ न रहे। एक फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें गति भी हो और लचीलापन भी ताकि वह अप्रत्याशित झटके सह सके। ऐसी योजनाओं की सफलता का पैमाना कम से कम जिले स्तर पर कीमतों में पैदा हुई विविधता होगी। अधिक जागरूकता तथा सामुदायिक दायित्व में वृद्धि अल्पकालीन हालातों से निपटने में मददगार साबित होगी। इससे वह मजबूती भी हमारे सामने आएगी जो खाद्यान्न व पोषण सुरक्षा के लिए मध्यावधि में व दीर्घकालीन स्तर पर चाहिए।

संदर्भ

[1] पीआईबी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 18 फरवरी 2020।

[2] एफसीआई वेबसाइट।

[3] लेखकों की गणना।

[4] कृषि मंत्रालय का 8 अप्रैल 2020 को वक्तव्य।

कोविड–19: वैश्विक बहुपक्षीय संबंधों के लिए नई आशा

आगस्टिन पीटर

विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019[1] में बहुपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई है । इस रिपोर्ट के अनुसार जहां एक और वैश्विक खतरे बढ़ रहे हैं वहीं उनसे निपटने की सामूहिक इच्छा शक्ति कमजोर दिखाई देती है उसमें काफी मतभेद हैं और ये मतभेद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इस बात को खास तौर से रेखांकित किया गया है कि विश्व राजनीति में राष्ट्रवाद में वृद्धि एक बढ़ता हुआ खतरा है।

कोविड–19 का आगमन और उसका प्रभाव

कोविड–19 महामारी अपने आप में अनूठी है क्योंकि इससे पूरी दुनिया लॉक डाउन में चली गई है जबकि इसके विपरीत कल तक यह हालत थी कि पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी तथा दुनियाभर में वैश्वीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। इस बदलाव के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। अंकटाड ने अपनी ट्रेड एंड डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट[2] में यह विश्लेषण किया है कि इस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आने वाली सिकुड़न जबरदस्त होगी।

क्या वैश्विक बहुपक्षीय संबंध बिखर रहे हैं?

कोविड–19 महामारी ने बहुपक्षीय संस्थाओं की स्थिति पर सबका ध्यान केंद्रित कर दिया है। जब यह समस्या उभर ही रही थी और पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर रही थी, लगभग 210 देश इससे प्रभावित हो चुके थे, तब भी महीनों तक इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मिलित प्रयास सामने नहीं आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बहुपक्षीय संगठन है जिस पर सबका ध्यान केंद्रित है । इसे लेकर दुनिया बुरी तरह से बंटी हुई है और इसकी प्रभाव क्षमता को लेकर इस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, साथ ही इस पर पक्षपातपूर्ण रवैए का आरोप भी लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले में न तो

कोई कार्ययोजना ही सामने रख पाई न ही उसने इस संबंध में कोई वक्तव्य जारी किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव भी अधिकतर लोगों को मात्र औपचारिकता भर ही लगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की धीमी तथा बंटी हुई प्रतिक्रिया ने इस बीमारी को महामारी में बदल दिया।

कैसे बदलें संकट को चुनौती में? क्या जी–20 उपयुक्त समाधान दे सकता है?

संकटों से ही कई बार अवसरों के द्वार खुलते हैं। संयुक्त राष्ट्र भी एक ऐसे संकट के कारण ही जन्मा था और जी–20 का जन्म भी 2008 में संकटों की बदौलत ही हुआ था। यूएन 75 एक अवसर उपलब्ध करवाता है जिसके माध्यम से दुनिया बहुपक्षीय प्रक्रियाओं के महत्व और उनकी उपयोगिता को दोबारा याद कर सकती है। जी–20 वास्तव में वैश्विक बहुपक्षीयता को स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ मंच है क्योंकि इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व है।

विजिटिंग फेलो, आरआईएस

इसमें थिंक टैंक्स (टी20), बिजनेस (बी20),लिंग समूह (डब्ल्यू20) सामाजिक संगठन (सी20) आदि शामिल हैं। क्या वैश्विक नेतृत्व इस अवसर पर आगे बढ़कर और इस त्रासदी को अवसर में बदलेगा जिससे वैश्विक बहुपक्षीय संबंध पुनः केंद्र में आ जाएं।

कोविड–19 के इस विषम संकट को लेकर एन ओ. क्रुगर[3] ने कहा कि पूर्व में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ऐसे संकटों का सामना करने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया दी थी लेकिन इस बार यह नदारद है। इस समस्या को लेकर जी–20 की प्रतिक्रिया भी बहुत धीमी है। अंततः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो मोर्चों पर महत्वपूर्ण पहल कीः एक, उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन (सार्क) सार्क का वर्चुअल सम्मेलन बुलाने की पहल की जिसमें सार्क देशों के सरकार अथवा राष्ट्राध्यक्ष[4] शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन में कोविड–19 आपात कोष को स्थापित करने का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सार्क के सदस्य देशों को कोविड–19 की चुनौती से निपटने के लिए सभी प्रकार की तकनीकी एवं वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत की रैपिड एक्शन फोर्स, कोविड–19 से जुड़ी आपात स्थितियों में मदद के लिए सभी सार्क देशों को उपलब्ध रहेगी। दो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जी–20 देशों को भी इसी प्रकार का शिखर सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया। यह सम्मेलन 26 मार्च 2020 को आयोजित हुआ। इसमें तय किया गया कि यह समूह विश्व अर्थव्यवस्था में 5 खरब अमेरिकी डॉलर डालेगा। एक वक्तव्य में जी–20 के नेताओं ने यह घोषणा की कि अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, यूएन, डब्ल्यूबीजी व अन्य के साथ मिलकर वे इस महामारी से निपटने के लिए जो भी करना चाहिए, वह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी–20 की इस प्रतिक्रिया को हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सकारात्मक रूप से नहीं देखा गया। गुड मैन (2020)[5] ने यह कहा कि मार्च 26 को जी–20 द्वारा जारी किया गया वक्तव्य मूलतः केवल उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहा था जो कि विभिन्न राष्ट्रीय सरकारें और केंद्रीय बैंक इन देशों में आक्रामक राजकोषीय और मौद्रिक नीति के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर करने का प्रयास पहले से ही कर रहे हैं। जी–20 के वक्तव्य में जिन प्रस्तावों की चर्चा की गई उनमें कोई विशिष्टता नहीं पाई गई, वे सामान्य प्रस्ताव थे[6]।

क्या जी–20 नेतृत्व कर सकता है?

जी–20 पुनः कैसे अपनी मजबूत स्थिति को स्थापित कर सकता है जहां वह समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना जाता था? वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं को पुनः स्थापित करने के लिए निम्न कदम उठाने होंगेः

- बहपुक्षीय संबंधों के विरोध तथा एकपक्षीय संबंधों के समर्थन में दिए जा रहे तर्कों का ठोस जवाब देना होगा
- उक्त बिंदु के संदर्भ में विभिन्न देशों व लोगों को बहुपक्षीय संबंधों के लाभ के बारे में बताना होगा। बहुपक्षीयता के अभाव में बड़ी शक्तियों के आस–पास शक्ति केंद्रित हो सकती है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कार्यकुशलता प्रभावित

होगी[7]। ऐसा नहीं है कि बहुपक्षीय व्यवस्था से होने वाला लाभ शून्य मात्र है[8]।

- बहुपक्षीय संगठनों में स्थितियों को समग्र रूप से सुधारना होगा। यूएन 75वीं वर्षगांठ के द्वारा पर होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र दशकों से ठहराव की स्थिति में है, यही हाल कमोबेश ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का भी है। बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की कहानी हालांकि कुछ और ही बताती है।
- किसी भी बदलाव को लाने में 'परिवर्तनकारी नेतृत्व' का महत्वपूर्ण हाथ होता है। व्यक्तियों और गठबंधनों में परिवर्तन लाना होगा। अमेरिका, चीन, युरोपीय संघ व भारत के रूप में एक 'क्वाड' का उभरना आवश्यक है। सामूहिक नेतृत्व समय की आवश्यकता है।
- वे समाधान जिनका प्रबंधन ठीक से किया जा सके तभी संभव होंगे अगर बहुपक्षीय संगठनों में ढांचागत परिवर्तन करते हुए महत्वाकांक्षाओं को तर्कसंगत सीमा के भीतर रखा जाए।
- जी–20 के सदस्यों को दोहा चक्र को पुनः जीवित करना होगा। इसके लिए उन्हें विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के सामने ऐसे समाधान व विकल्प रखने होंगे जो स्वीकार्य हैं। एजेंडा भी ऐसा बनाना होगा जो निष्पक्ष हो ताकि उस पर चर्चा हो सके।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुएत्रेसवास ने बड़ी बेबाकी से यह कहा[9] कि बहुध्रुवीय दुनिया समाधान नहीं है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि बहुपक्षीय प्रक्रियाओं के महत्व को स्थापित करना जरूरी है। यह स्पष्ट है कि बहुपक्षीयता के रास्ते से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जी–20 वह प्लेटफार्म है जो इस बहस को उस दिशा में आगे ले जा सकता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और भारत इन चारों को मिलाकर एक नया 'क्वाड' समूह बनना जरूरी है जो आपस में चर्चा करें तथा जी–20 को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए दिशा प्रदान करें।

एंडनोट्स

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdfaccessedon 06-04-3-2020

2 अंकटाड (2020), द कोविड–19 शॉक टू डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्डस ए 'व्हाटएवर इट टेक्स प्रोग्राम' फॉर द टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पापुलेशल लेफ्ट बिहाइंड

3 ऐनी ओ क्रुएगर, ओन्ली मल्टीलेट्रिस्म कैन सेव अस, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 19 मार्च, 2020 यहां उपलब्ध हैः https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-only-multilateral-response-can-work-by-anne-krueger-2020-03accessed on 05-04-2020

4 https://www.narendramodi.in/prime-minister-narendra-modi-s-interaction-with-saarc-leaders-on-fighting-coronavirus-548793, accessed on 06-04-2020 Accessed on 06-04-2020

5 मैथ्यू पी. गुडमैन , स्टीफेनी सीगल एंड मार्क सोबल(2020), असेससिंग द जी20 वर्चुअल समिट, सेंटर फार स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, यूएसए, यहां उपलब्ध हैं https://www.csis.org/analysis/assessing-g20-virtual-summit accessed on 05-04-2020

6 हर्ष वी पंत, ए रिडंडेंट जी20, रायसीना डिबेट, मार्च 30,2020, ओआरएफ:https://www.orfonline.org/expert-speak/a-redundant-g20-63859/accessed on 06-04-2020

7 दादूश एंड गुन्तराम बी. (2019)

8 https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/

9 https://www.weforum.org/agenda/2019/01/these-are-the-global-priorities-and-risks-for-the-future-according-to-antonio-guterres

संदर्भ

दादूश, उरी एंड वुल्फ, गुन्तराम बी.(2019), लाइफ आफ्टर द मल्टीलेट्रल ट्रेडिंग सिस्टम, ग्लोबल इकोनोमिक्स एंड गवर्नेंस, अप्रैल 25,2019, यहां उपलब्ध है: available at: https://www.bruegel.org/2019/04/life-after-the-multilateral-trading-system/ accessed on 07-04-2020

मैथ्यू पी. गुडमैन , स्टीफेनी सीगल एंड मार्क सोबल(2020), असेससिंग द जी20 वर्चुअल समिट, सेंटर फार स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, यूएसए, यहां उपलब्ध हैः https://www.csis.org/analysis/assessing-g20-virtual-summit accessed on 05-04-2020

हर्ष वी पंत, ए रिडंडेंट जी20, रायसीना डिबेट, मार्च 30,2020, ओआरएफ, यहां उपलब्ध हैः https://www.orfonline.org/expert-speak/a-redundant-g20-63859/accessed on 05-04-2020

ऐनी ओ क्रुएगर, ओन्ली मल्टीलेट्रिस्म कैन सेव अस, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 19 मार्च, 2020 यहां उपलब्ध हैः https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-only-multilateral-response-can-work-by-anne-krueger-2020-03 accessed on 05-04-2020

अंकटाड (2020), द कोविड–19 शॉक टू डेवलपिंग कंट्रीजः टुवर्डस ए 'व्हाटएवर इट टेक्स प्रोग्राम'

संयुक्त राष्ट्र महासचिव, श्री एंटोनियो गुटेरेस गटरेस द्वारा दिया गया भाषण, फ्रेगमेंटेड रिस्पॉन्स टू ग्लोबल सिस्क ऐ रेसिपी फॉर डिजास्टर, दावोंस–क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड, प्रकाशित 24 जनवरी, 2019, यहां उपलब्ध हैः Available at:https://www.weforum.org/press/2019/01/un-secretary-general-fragmented-response-to-global-risk-a-recipe-for-disaster/, accessed on 06-04-2020

विश्व आर्थिक फोरम, बहुपक्षीयता क्यों इतनी समस्या में है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं; बहुपक्षीयता की असफलता का एक कारण वैश्वीकरण से मोहभंग होना भी है; यहां उपलब्ध हैः https://www.weforum.org/agenda/2020/01/why-multilateralism-is-in-such-a-mess-and-how-we-can-fix-it/, accessed on 06-04-2020

सुधार पैकेज: कोविड–19

सुभोमॉय भट्टाचार्जी

मौजूदा हालात में अभी यह कहना मुश्किल है कि सरकार राजकोषीय घाटे में वृद्धि को कितना अधिक वहन कर सकती है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इस घाटे में वृद्धि को अर्थव्यवस्था में ऋण की वृद्धि के संदर्भ में मापना होगा।

विकसित देशों के लिए कोई समस्या नहीं है भले ही उनकी ब्याज दर शून्य के आसपास हो और उनका राजकोषीय घाटा काफी ज्यादा भी हो, इसके बावजूद उन्हें ऋण व्यवस्था स्थिर को बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था को गंभीर समस्या हो सकती है अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा हो जाए, ब्याज दरें भी बढ़ जाएं और जीडीपी की विकास दर गिर जाए ऐसे में ऋण स्थिति को स्थिर बनाए रखना अपने आप में एक मुद्दा बन सकती है। ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर आरबीआई ने अतिरिक्त रूप से जारी हुए सरकारी बॉन्ड्स को नकदी में बदल दिया।

कहा जा सकता है कि कई सेक्टरों को आर्थिक मदद देना जरूरी है लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए यह भी जरूरी है कि कीमतों के संकेतों को तथा सोच समझ कर किए गए सुधारों को इस्तेमाल किया जाए। यह कदम सभी सेक्टरों के लिए उठाए जाने चाहिए जिसमें लघु व मध्यम दर्जे के उद्यम भी शामिल हैं।

एक आसान उदाहरण से शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इस समय मास्क और पीपीई की जबरदस्त कमी है। लेकिन सरकार के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह इसका उत्पादन शुरू कर दें। वह बेकार में ही कई प्रकार की औपचारिकताओं में फंस जाएगी। इससे ज्यादा बेहतर तो यह होगा कि वह कीमत तंत्र पर इस प्रकार से निर्भर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मैनुफैक्चरर्स को इनका उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिले और ऐसा करते हुए वे इन उत्पादों से संबंधित आवश्यक नियमों का कड़ाई से पालन करें।

इसी प्रकार प्रवासी मजदूरों की वापसी भी तभी होगी अगर उनके पुराने नियोक्ता उन्हें वापस बुलाते हैं। पर उन नियोक्ताओं के पास नकदी की कमी है और वे आरंभ में लोगों को वेतन नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे। ऐसे में एक मध्यावधि कदम के तौर पर सरकार शहरी कार्यों के निर्माण का एक ऐसा कार्यक्रम चला सकती है जिसमें इस प्रवासी श्रम शक्ति को रोजगार दिया जाए। पर इन सुविधाओं का निर्माण केवल शहरी गरीबों के रहने के लिए किया जाना चाहिए। चूंकि युवा कोविड–19 के खतरे से इतने अधिक प्रभावित नहीं हैं इसलिए 16 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को इस काम में जोड़ा जा सकता है इनमें से अभी 10 प्रतिशत से भी कम कामकाजी हैं। इससे श्रम शक्ति में पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होगा। तो इस प्रकार यह प्राथमिकताएं निम्न हैं:

1. सरकार को लंबे समय तक धीमे आर्थिक विकास के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बेहतर होगा कि वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एक बजट दोबारा तैयार किया जाए। इससे अर्थव्यवस्था को स्थायित्व मिलेगा।
2. तार्किक आधार: भारत सरकार पर इस बात का भारी दबाव है और आगे भी इस बात का दबाव रहेगा कि वह सभी सेक्टरों को वित्तीय मदद उपलब्ध करवाए। लेकिन ऐसा करते समय अल्पकालीन तथा मध्यावधि मदद में फर्क करना जरूरी है। इस अंतर के माध्यम से फौरी दबावों को भी झेला जा सकेगा तथा दीर्घ काल के लिए योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। इस प्रकार का अंतर इस बात का भी स्पष्टीकरण करेगा कि भारत सरकार क्या करने जा रही

वरिष्ठ विशिष्ट फैलो, आरआईएस

है और क्या नहीं करेगी। इसका परिणाम यह होगा कि इससे विदेशी संस्थागत निवेशक आश्वस्त होंगे और हमारी सार्वभौमिक सेटिंग्स को बेहतर करने में मदद मिलेगी और इसलिए सभी को आश्वासन मिलेगा कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के प्रयास दो साल तक बिना रुके जारी रहेंगे। इसलिए दो साल का विशेष बजट जरूरी है।

अगर सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य में अत्यधिक निवेश करती है तो उसे भारी लाभ होगा। इसमें निविदाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से विचार करना और स्वास्थ्य वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अपूर्ति आदेश शामिल होंगे। इस तरह के आदेश इन सामानों के उत्पादन को तुरंत प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन कोई मूल्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक अवैध अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा करेगा।

तार्किक आधार – भारत सरकार को इसके लिए निम्न योजना बनानी चाहिएः

- बड़े पैमाने पर एक अर्धचिकित्सा बल का निर्माण। यह एक वर्ष में पूरा नहीं होगा, लेकिन भविष्य की महामारियों को रोकने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह एक मूल्यवान कदम होगा।
- सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ उपजिला स्तर पर अस्पतालों का निर्माण करना। इन अस्पतालों के लिए मानक स्थापित करना तथा क्षेत्रीय हवाई अड्डों की योजना की तर्ज पर इनकी नीलामी करना। (यह मुश्किल तो है पर निजी क्षेत्र के लिए इसे फायदेमंद बनाने हेतु यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किन मदों में शुल्क देना होगा तथा कौन सी मदें निशुल्क हैं।)
- भारत में महामारियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दवा श्रृंखलाएं बनाना। इसके लिए जन औषधि योजना को अंतिम सिरे तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हुए निजी क्षेत्र से भारी मात्रा में दवाएं खरीदना।
- एक स्वास्थ्य नियामक की स्थापना (आईआरडीए ने भी इसके बारे में कहा है।)

3. क्या हम कोविड–19 के लिए स्वैच्छिक जन परीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कम आय वाले (प्रति व्यक्ति 2000 रुपये प्रति व्यक्ति) परीक्षण वाउचर की पेशकश कर सकते हैं?
   - तार्किक आधारः इस वाउचर को केवल शहरी क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। नगरों में किराना दुकानें आसानी से उपलब्ध हैं और उन पर नजर रखी जा सकती है कि वे गड़बड़ी न करें। समानांतर पीडीएस बनाने की जरुरत नहीं है। ये वाउचर वर्चुअल होने चाहिएं और उसी को दिए जाएं जो यह प्रमाणित कर सके कि उन्होंने अपना काविड19 का टेस्ट करवाया है। इससे एक राष्ट्रीया चिकित्स व भोजन सुरक्षा तंत्र तैयार हो जाएगा।
4. सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिनमें निरंतरता है और हाइड्रॉक्सिकोलोरोक्वाइन टैबलेट के निर्यात पर अल्पावधि प्रतिबंध की तरह अचानक दी जाने वाली प्रतिक्रिया से बचें।

मध्यावधि प्राथमिकताएं:

- भारत सरकार को डिजिटल भारत का लाभ उठाना चाहिए तथा चौथी पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति की तैयारी करनी चाहिए। सरकार की नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे स्वास्थ्य व फार्म सैक्टर कंपनियों को सरकार के साथ दीर्घकालीन अनुबंध करने में मदद मिलें।
- भारत सरकार ने स्थाई वित्तीय आर्थिक नीतिगत सुधारों को बढ़ाकर ठीक कदम उठाया है क्योंकि इससे बाजार में तरलता बनी रहेगी। उसे इस नीति पर बने रहना चाहिए। मसलन अगले दो सालों के लिए मुद्रास्फीति में परिवर्तन को अपना लक्ष्य बनाने संबंधी योजनाओं में बदलाव को रोक देना चाहिए ।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे लघु व मध्यम उद्योग तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को अधिक से अधिक ऋण दें। हालांकि आरबीआई ने स्पष्टीकरण दे दिया है लेकिन इसके बावजूद कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इन उद्ममों व संस्थाओं को ब्याज व ऋण अदायगी पर दी गई छूट का पालन नहीं कर रही हैं।
- जीएसटी के रेट कम किये जाए तथा इसे दो दरों वाली सरल व्यवस्था के करीब लाया जाए। चूंकि वित्त वर्ष 2021 में कर राजस्व कम होने वाला है इसलिए जीएसटी में बड़े बदलाव करने का यह उचित समय है। यह तेल व कायेला सेक्टर को जीएसटी के अंतर्गत लाने का समय है। इन दोनों कदमों से जो पैसा आएगा वह कमजोर वर्ग के परिवारों के हाथ में दिया जा सकता है जो केरोसिन एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में सीधे गिरावट को अनुभव करेंगे। परिवहन की लागत में कमी के कारण अन्य सभी वस्तुओं पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और उनके दामों में कमी आएगी। इसके अलावा यह एक ऐसा ढांचागत सुधार है जो काफी समय से लंबित था।
- समय आ गया है कि 1897 के महामारी रोग अधिनियम को समाप्त किया जाए और एक ऐसा कानून लाया जाए जो भारतीय संविधान की भावना के अनुरुप है। उसमें पर्याप्त मात्रा में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रावधान होना चाहिए।
- इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नियामक की स्थापना की जा सकती है इसके साथ ही निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे जांच केंद्रों को अथवा सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय आंकड़ों की स्थिति को सुधारा जा सकता है।

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, भारत । दूरभाष: 91-11-24682177-80
फैक्स: 91-11-24682173-74, ई-मेल: **dgoffice@ris.org.in**
वेबसाइट: **http://www.ris.org.in**

Follow us on:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादक: तीश मल्होत्रा